अस्वीकरण

यह पूर्ण दस्तावेज़ का सारांश संस्करण है। पूर्ण दस्तावेज http://seci.co.in/web-data/docs/RAP%20TL%20Draft.pdf पर प्राप्त किया जा सकता है।

किसी भी विसंगति / अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) - ट्रांसमिशन लाइन
कार्यकारी सारांश

1.1 परिचय

सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका इरादा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रामगिरी और मुथुवाकुंतला गांव में ऊर्जा भंडारण सुविधा सहित 160 मेगावॉट ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता की पवन-सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजना विकसित करना है।

सौर-पवन हाइब्रिड पार्क के लिए 'सौर ऊर्जा और हाइब्रिड प्रौद्योगिकी (आईएसपीएचटी) परियोजना में नवीकरण' के इसके एक भाग के रूप में विश्व बैंक से विशेष ऋण की सहायता दी गई है। परियोजना का स्वामित्व सेकी के पास रहेगा और परियोजना के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा सेकी द्वारा आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की पूर्व सहमति से दीर्घकालिक विद्युत खरीद करार के माध्यम से आंध्र प्रदेश डिस्काम को बेची जाएगी।

1.2 परियोजना विवरण

प्रस्तावित सौर-पवन हाइब्रिड विद्युत परियोजना में 120 मेगावॉट क्षमता वाले सौर पीवी फार्म, 40 मेगावॉट क्षमता का पवन फार्म की स्थापना, बैटरी भंडारण सुविधा और रामगिरी पूलिंग स्टेशन से हिंदुपुर ग्रिड तक लगभग 45 किलोमीटर लम्बी ट्रांसमिशन लाइन शामिल है। प्रस्तावित सौर-पवन हाइब्रिड पार्क आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के रामगिरी गांव (मंडल - रामगिरी) और मुथुवाकुंतला (मंडल- कनगनापल्ली) में पड़ता है । पहचान किए गए स्थल की भौगोलिक स्थिति 14o21 '29.7 "उत्तरी अक्षांश और 77o31' 18.9" पूर्वी रेखांश है। यह आरएपी विशेष रूप से 45 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के लिए है।

1.3 कार्यप्रणाली

कार्य योजना प्राथमिक और माध्यमिक डेटा स्रोतों की समीक्षा पर आधारित है। भू-खंड जो ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित होंगे, की पहचान करने के लिए संरेखण के पैमाने में परिवर्तन करके राजस्व मानचित्र पर संरेखण अध्यारोपित किया गया था। एक बार भू-खंड की पहचान हो जाने के बाद, भूमि अभिलेखों से स्वामित्व के विवरण प्राप्त किए गए थे। व्यापक आधारभूत स्थिति और स्थानीय समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने और परियोजना प्रभावित परिवारों / लोगों के कानूनी हकदारी को स्थापित करने के लिए गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किए गए थे। वास्तविक स्थिति का पता लगाने / सत्यापित करने और परियोजना क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं, भौतिक विशेषताओं

और सांस्कृतिक सेट-अप का पता लगाने के लिए विभिन्न एजेंसियों से माध्यमिक डेटा / जानकारी एकत्र की गई थी।

1.4 भूमि की आवश्यकता

प्रस्तावित हाइब्रिड पार्क के लिए कुल 389.02 एकड़ भूमि की आवश्यकता है जिसमें आरओडब्ल्यू के अधीन भूमि 379.02 एकड़ होगी और अन्य 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता टॉवर फुटिंग के लिए होगी। आरओडब्ल्यू और टॉवर फुटिंग दोनों के तहत आने वाले खंड निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि और खेती के अधीन हैं। ट्रांसमिशन लाइन उप परियोजना के कारण कुल 333 परिवारों पर असर पड़ेगा।

1.5 परियोजना क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 73,674 है जिसमें 51.43% पुरुष हैं और 48.57% महिलाएं हैं। अध्ययन क्षेत्र का औसत लिंग अनुपात लगभग प्रति 1000 पुरुष 944 महिलाएं हैं, जो प्रति 1000 पुरुषों 933 महिलाओं की राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी बेहतर है। कुल अध्ययन क्षेत्र ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अध्ययन क्षेत्र की पूरी जनसंख्या को 17,544 घरों में बांटा गया है और औसत घरेलू आकार लगभग 4.12 व्यक्ति / घर है। अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 18.81% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 15.10% है और 3.71% अनुसूची जनजाति समुदाय से संबंधित है।

अध्ययन क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 53.21% (18.091) है जिसमें पुरुष जनसंख्या के संबंध में पुरुष साक्षरता 61.85% है जबकि महिला जनसंख्या के संबंध में महिलाओं की साक्षरता 44.18% है जिसमें लिंग अंतर 17.67% बैठता है। काम करने वाले व्यक्तियों के औद्योगिक वर्गीकरण पर जनगणना डेटा दर्शाता है कि 38.03% किसान हैं, 45.70% हैं कृषि मजदूर, 1.71% घरेलू उद्योग में नियोजित हैं और 14.57% अन्य कामगारों की श्रेणी में आते हैं।

1.6 नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करना

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) ने आरओडब्ल्यू और टावर फुटिंग द्वारा प्रभावित लोगों पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों की पहचान की है । विस्थापन से बचने के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन संरेखित किसी भी बस्ती में से न जाए।

1.7 सामुदायिक भागीदारी और परामर्श

प्रस्तावित परियोजना के बारे में हितधारकों को सूचित और शिक्षित करने और परियोजना डिजाइन पर समुदाय के सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से परियोजना के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में जनता से परामर्श किया गया था। इसने

परियोजना से जुड़े मुद्दों और प्रभावित समुदाय की जरूरतों की पहचान करने में सहायता की थी।

1.8 लागू नीतियां और आर एंड आर ढांचा

आरएफसीटीएलएआरएण्डआर अधिनियम, 2013 और पुनर्वास और पुन:स्थापन के सम्बंध में विश्व बैंक के दिशानिर्देश दोनों का उद्देश्य सभी व्यवहार्य वैकल्पिक परियोजना डिजाइनों का पता लगाते हुए, जहां भी संभव हो, अनैच्छिक पुनर्वास से बचना या न्यूनतम करना है। ऐसे मामलों में जहां विस्थापन अपरिहार्य है, संपत्ति, आजीविका या अन्य संसाधनों को खोने वाले लोगों को उनकी किसी अतिरिक्त लागत के बिना कम से कम उनकी पूर्व जीवनयापन स्थिति लाने में सहायता की जाएगी। चूंकि भूमि अधिग्रहण नहीं की जाएगी और प्रभाव आरओडब्ल्यू के तहत भूमि के प्रतिबंधक उपयोग के कारण होगा, टावर और ट्रांसमिशन लाइनों के लिए सही मार्ग के कारण क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश लागू होंगे। दिशानिर्देशों में टावर फुटिंग के लिए भूमि की हानि के लिए 100 प्रतिशत मुआवजे और आरओडब्ल्यू के तहत भूमि के लिए मुआवजे मूल्य के 10% की व्यवस्था है।

1.9 परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी)

5 मंडलों के 1,660 सदस्यों सहित 333 परिवारों के स्वामित्व वाले कुल 253 भूखंड ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित हो रहे हैं। औसत परिवार का आकार 4.16 बैठता है।

1.10 संस्थागत व्यवस्था और कार्यान्वयन योजना

आरएपी योजना के कार्यान्वयन के लिए उचित संस्थागत व्यवस्था के लिए एक विस्तृत तंत्र प्रदान करता है। सेकी / एपीटीआरएएनएससीओ के निगमित कार्यालय में एक पर्यावरण और सामाजिक अधिकारी होगा जिसकी सहायता के लिए एक क्षेत्रीय अधिकारी और परियोजना डेवलपर्स का एक प्रतिनिधि होगा। एपीटीआरएएनएससीओ का क्षेत्रीय अधिकारी परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली किसी भी तरह की शिकायतों के लिए संपर्क का पहला स्तर भी होगा। यह परिकल्पना की गई है कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की गतिविधियां परियोजना शुरू होने के 15 महीने के अन्दर पूरी की जाएंगी।

1.11 शिकायत निवारण तंत्र

विवादों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक तीन-स्तरीय उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। परियोजना स्तर, राज्य और सेकी में आवश्यक जनशक्ति सहित एक एकीकृत प्रणाली स्थापित की जाएगी। शिकायतें, यदि कोई हों, तो विभिन्न माध्यमों, व्यक्तिगत रूप से, संबंधित पते पर लिखित रूप में, ई-मेल या संबंधित अधिकारियों को सीधी कॉल के जरिए प्रस्तुत की जा सकती हैं।

1.12 कार्यान्वयन अनुसूची

सिविल कार्य कार्यान्वयन अनुसूची से स्पष्ट रूप से सम्बद्ध पुनर्वास कार्यान्वयन अनुसूची सहित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का एक विस्तृत कार्यान्वयन अनुसूची को आरएपी में शामिल किया गया है। भूमि और संबंधित परिसंपत्तियों का अधिग्रहण मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही किया जाएगा, और जहां लागू हो, पुनर्वास स्थल और विस्थापन भत्ते की पीएपी में व्यवस्था की गई है। कार्यान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और अनुभवी कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी कि आरएपी को अनुमोदित अनुसूची के अनुसार सुचारु रूप से लागू किया जाता है।

1.13 प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और आय बहाली

पुनर्स्थापन कार्य योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने का उद्देश्य नकारात्मक प्रभाव को कम करना और परिवर्तनों को सकारात्मक बनाना है। आरएपी के उद्देश्यों का एक उद्देश्य पूर्व परियोजना स्तर, यदि नहीं बढ़ाया गया है, पर पीएपी की आजीविका स्थितियों को बहाल करना है। दूसरे शब्दों में, परियोजना के तहत आजीविका की बहाली और वृद्धि का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना होगा कि पीएपी कम से कम उनके पूर्व जीवन यापन स्तर को वापस पाने में सक्षम हो। सलाहकारों ने कुछ आय सृजन योजनाओं की पहचान की है और लघुसूचीयन किया है।

1.14 निगरानी और मूल्यांकन

कार्य योजना निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) के प्रावधान स्थापित करती है। सेकी आरएपी कार्यान्वयन की आंतरिक निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा जबकि बाहरी एजेन्सी को आरएपी कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए काम पर लगाया जाएगा ।

1.15 लागत और बजट

बजट स्वरूप में संकेतक है और इसमें विभिन्न व्यय श्रेणियों के लिए परिव्यय शामिल है जिनकी गणना मौजूदा मूल्यों पर की गई है। लागत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना / राजस्व विभाग डेटा और वर्तमान बाजार मूल्यों के माध्यम से एकत्र की गई सूचना पर आधारित है। आरएपी कार्यान्वयन का बजट लगभग 5.30 करोड़ रुपये है।

सेकी के अधीन ईएसएमएफ के प्रावधानों की हकदारी के अनुसार पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) के लिए अनुमानित लागत

क्र.सं.	मदें	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रुपये में)	सरकारी आदेश के अनुसार दर	कुल राशि (रुपये)
1	पाइलॉन के लिए भूमि	एकड़	10.00	500000	100%	5000000
2	स्ट्रिगिंग के लिए भूमि	एकड़	379.02	500000	10%	18951000
	उप-जोड़					**23951000**
3	आजीविका बहाली	पीएएफ	225	10000		2250000
	आर एंड आर सहायता	पीएएफ				
4	निर्वाह भत्ता	पीएएफ	333	36000		11988000
5	दोषपूर्ण पीएएफ के लिए एक बार अनुदान	पीएएफ	50	50000		2500000
6	आरएपी कार्यान्वयन एजेंसी को काम पर रखना		एकमुश्त			4000000
7	आरएपी के मध्य अवधि और अंतिम अवधि मूल्यांकन के लिए एजेंसी को काम पर रखना		एकमुश्त			3000000
8	जीआरसी की स्थापना की लागत		एकमुश्त			500000
	उप जोड़					**24238000**
	जोड़					**48189000**
	आकस्मिकता		**10%**			**4818900**
	कुल जोड़					**53007900**

नोट: आरओडब्ल्यू के लिए प्रति सरकारी आदेश मुआवजे की गणना। दिनांक-20.06.2017